प्रसव हेतु तिगांव से आई महिला बीके अस्पताल में रिश्वत देने के बावजूद बनी घोर लापरवाही का शिकार

फ़रीदाबाद (म.मो.) रविवार, दिनांक 25 फ़रवरी को कोमल नामक महिला को सुरक्षित प्रसव हेतु, 20 किलोमीटर दूर, तिगांव से ज़िले के सबसे बड़े सरकारी बादशाहखान अस्पताल में लाया गया। महिला वार्ड में भर्ती होते ही अपनी आदत के मुताबिक माला व रजनी नामक दो नर्सों ने कोमल की सास से 2000 रुपये की मांग कर डाली। सास ने 1000 रुपये देते हुए कहा कि शेष प्रसव उपरांत दे देगी। लेकिन वे दोनों हज़ार रुपये लेकर संतुष्ट नहीं हुई। उनका कहना था कि 2000 तो दाखिल होने व बेड आदि के हैं प्रसव उपरांत तो वे 'बधाई' अलग से लेंगी।

उनकी अयसन्तुष्टि का परिणाम यह निकला कि सोमवार सुबह करीब 7 बजे जब कोमल को ज़ोरदार प्रसव पीड़ा हुई तो उन दोनों नर्सों ने उसे बेड से लेजा कर लेबर रूम की टेबल, जो सामान्य बेड से करीब डेढ फुट ऊंची होती है, पर बैठा दिया और खुद डॉक्टर को बुलाने के बहाने से कमरे के बाहर बतियाने लगी। करीब 5-7 मिनट बाद प्रसव पीड़ा और बढी, कोमल चिल्लाई, लेकिन नर्सों ने उस ओर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी। इस बीच प्रसव हो गया। कोमल खुद इस स्थिति में नहीं थी, वही क्या कोई भी महिला ऐसे में अपने नवजात शिशु को सम्भाल पाने की स्थिति में नहीं हो सकती, लिहाजा नवजात कोख से निकल कर सीधा फ़र्श पर रखे कूड़ेदान में जा गिरा।

सेक्टर 3 का जच्चा-बच्चा अस्पताल

एक एकड़ के प्लॉट में बनी इस दुमंजली इमारत के अलावा 6 स्टाफ़ क्वार्टर हैं जिनमें स्टाफ़ रहते हैं। इस अस्पताल में 4 डॉक्टर व 4 नर्सों को मिला कर कुल 30 लोग़ों का स्टाफ़ है। इसके बावजूद तिगांव से डिलिवरी हेतु आई कोमल को बीके अस्पताल रैफ़र कर दिया गया, तो फ़िर यह इतने बड़े ताम-झाम पर जनता का पेसा क्यों बहाया जा रहा है?

इस पर जब ज़्यादा हो हल्ला मचा तो वे दोनों नर्सें कोमल के पास आई और उल्टा उसे ही धमकाने लगी कि थोड़ी देर रूक नहीं सकती थी। पीड़ित महिला को डांटने के बाद उन्होंने एक और सफ़ेद झूठ बोला कि उन्होंने तो प्रसव करा कर नवजात को उसकी मां की बगल में लिटा दिया था। विदित है कि लेबर रूम की टेबल पर इतनी जगह ही नहीं होती कि नवजात को उसके पास लिटाया जा सके; दूसरे, नवजात को मां के पास लिटाने से पूर्व उसे नहला-धुला कर साफ़ किया जाता है और मां को वार्ड में शिफ़्ट करके बेड पर लिटाया जाता है।

कूड़ेदान में गिरे बच्चे को जो अन्दरूनी चोटें लगी उनका हरियाणा सरकार के इतने बड़े इस अस्पताल में कोई इलाज उपलब्ध नहीं होने के चलते बच्चे को सफ़दरजंग अस्पताल दिल्ली रैफ़र कर दिया, जैसा कि यह अस्पताल रोजाना पचासों बार करता है। विदित है कि दिल्ली के उस अस्पताल में मरीज़ों की इतनी भीड़ है कि उन्हें फ़र्श पर भी लेटना पड़ता है। खैर जैसे-तैसे इस नवजात को वहां के डॉक्टरों ने सम्भाला और दो दिन के उपचार के बाद फ़ारिग कर दिया।

बीके अस्पताल में हुए इस कांड के मीडिया में छा जाने के चलते गहन मजबूरी में अस्पताल प्रशासन को जांच का नाटक करना पड़ा। नाटक खेलने के लिये तीन डॉक्टरों की एक कमेटी का गठन किया गया। जांच रिपोर्ट भी जो कभी नहीं आती, इस बार तुरन्त आ गयी। दोनो नर्सों को दोषी ठहराया गया; परन्तु उनके ऊपर तैनात ड्यटी डॉक्टर अपर्णा गुप्ता उस वक्त कहां थी और उसने क्या भूमिका निभाई? इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जांच कमेटी गोल कर गयी।

इतने गंभीर अपराध के लिये दोषी पाई गयी दोनों नर्सों के विरुद्ध कार्यवाही के नाम पर उन्हें महिला (प्रसूति) वार्ड से हटा कर दूसरे वार्डों में डाल दिया गया। ये दोनों नर्सें क्योंकि **'नेशनल हैल्थ मिशन'** के तहत आती हैं, इस लिये इनके विरुद्ध और कोई कार्यवाही सिविल सर्जन गुलशन अरोड़ा जी करेंगे। अरोड़ा जी कोई चंडीगढ नहीं बैठते, वे भी इसी बीके अस्पताल में बैठते हैं, उन्हें भी सब कुछ साफ़-साफ़ दिखाई देता है, बशर्ते कि वे देखना चाहें तो।

फिलहाल वार्ड बदलने को ही एक बड़ी कार्यवाही माना जा रहा है क्योंकि ये दोनों नर्सें बरसों से प्रसूति वार्ड में और वह भी रात की ड्यूटी में रहती आ रही हैं। इस ड्यूटी में रोज़ाना 5-10 हज़ार की लूट कमाई ये नर्सें करती आ रही हैं। इस कमाई के अलावा जो बद्तमीज़ी ये मरीज़ों के साथ करती हैं उसका तो काई हिसाब नहीं। रात की ड्यूटी में अधिक कमाई का एक और कारण यह भी है कि ड्यूटी डॉक्टर मजे से घर में सोती रहती है और डॉक्टरी का काम भी ये खुद ही कर लेती हैं, यहां तक कि दूसरे अस्पतालों को रैफ़र करने तक का काम भी ये ही निपटा देती है।

यह संभव नहीं कि बरसों से चल रहा यह गुलगपाड़ा सिविल सर्जन अरोड़ा को न पता हो। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब इस वार्ड से शिकायतें न आती हों और अरोड़ा जी 'जांच' का आश्वासन देकर मामले को रफ़ा-दफ़ा न कर देते हों। मतलब स्पष्ट है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अरोड़ा जी के संरक्षण एवं हिस्सा-पत्ती में ही हो रहा है।

एमसीएफ़ में नये घोटाले की तैयारी, प्रतापगढ़ में 245 करोड़ का नया एसटीपी बनेगा, पुराना हुआ मिट्टी

फ़रीदाबाद (म.मो.) सीवरेज के गंदे परनी का एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) द्वारा ट्रीट करके सिंचाई हुतु छोड़े जाने के लिये प्रतापगढ़ में 50 एमएलडी (मिलयन लीटर प्रतिदिन) क्षमता का प्लांट लगाने की सख्त आवश्यकता को देखते हुए 245 करोड़ रुपये की योजना बनाई गयी है। एनआईटी क्षेत्र की करीब 5 लाख आबादी को सड़ते व उफ़नते सीवरों से निजात दिलाने के लिये क्षेत्र के पांचों पार्षदों ने नगर निगमायुक्त पर भारी दबाव बनाकर इस प्रस्ताव को स्वीकृत कराया है।

पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से सीवेज का एक बूंद पानी भी बिना ट्रीट अर्थात बिना शुद्ध किये किसी नदी, नहर या रजबाहे में नहीं डाला जाना चाहिये। इसी नीति के चलते करीब 30 वर्ष पूर्व सरकार ने यमुना एक्शन प्लान व अन्य योजनाओं के तहत हज़ारों करोड़ खर्च करके 3 प्लांट लगाये थे। उन्हीं में से एक प्रतापगढ़ में भी लगाया गया था जो एक दिन भी नहीं चला और खड़ा-खड़ा ही मिट्टी हो गया। शेष दोनों प्लांट-बादशाहपुर व मिर्जापुर गांव में लगे हैं।

इन प्लांटों ने गांव वालों का जीना दूभर कर रखा है क्योंकि ये प्लांट लगभग नाकारा हैं। गांवों के आसपास गंदा पानी सड़ रहा है, दुर्गन्ध के मारे बुरा हाल है। यह दुर्दशा तो इन दोनों प्लांटों की तब है जब वहां पूरा सीवेज पहुंचता ही नहीं, अधिकांश तो गुड़गांव व आगरा नहरों व यमुना नदी में सीधा बहा दिया जाता है।

इन तीनों प्लांटों की मशीनरी, परिचालन एवं रख-रखाव तो जैसा है सो है, इन प्लांटों तक सीवेज को भेजने की पाइप लाइन व्यवस्था भी एकदम नाकारा है। सीवेज को प्लांटों तक धकेलने वाले बूस्टर स्टेशनों की न तो मोटरें ठीक से काम करती हैं और न ही पाइप लाइनें किसी काम की हैं; हां इसके कागज़ी रख-रखाव पर आये दिन मोटे बिल जरूर बनते रहते हैं।

प्रतापगढ वाले प्लांट का हाल सबसे बुरा उसी दिन से रहा है जिस दिन से यह बना है क्योंकि इस प्लांट पर कार्यभार दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया और इससे जुड़ी आबादी (जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी आदि) में अधिकांश भाग समाज के सबसे दबे-कुचले एवं वंचित वर्ग का है। सरकार एवं अफ़सरशाही में इस वर्ग की सुनवाई ना के बराबर ही रहती है। इसके चलते इनकी गलियों में उफ़नते सीवरों का पानी अक्सर बहते देखा जा सकता है।

प्रतापगढ के लिये एसटीपी तो जरूर बनना चाहिये परन्तु वह चलना भी तो चाहिये, खाली बनने व उसके नाम पर 245 करोड़ डकारने से क्या होगा? पहले जो पलांट लगा था उस पर भी तो जनता का सैंकड़ों करोड़ लगा था, उसे कौन डकार गया? डकारने की यह प्रथा कोई नई अथवा यदा-कदा होने वाली घटना नहीं है; अभी तीन-चार वर्ष पूर्व ही बंधवाड़ी में 70 करोड़ की लागत से ठोस कचड़ा निस्तारन प्लांट लगाया गया था, पिछले वर्ष उसमें आग लगा कर जनता के 70 करोड़ को मिट्टी बनाने में देर नहीं लगी। और तो और इसके लिये किसी को दोषी अथवा ज़िम्मेवार भी नहीं ठहराया गया।

प्रसूति वार्ड से रिश्वत की एक और शिकायत: जांच कमेटी गठित

इसी सप्ताह बनी बीके की एक जांच कमेटी की रिपोर्ट की स्याही सूखी भी नहीं थी कि 28.2.18 को फ़िर से 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन डॉ. गुलशन अरोड़ा ने कर डाला। इस बार शिकायतकर्ता थी गर्भवती सोनी की सास उर्मिला जो मेवला महाराजपुर से बहू की डिलिवरी कराने आई थी।

वार्ड में मौजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मरीज़ के आते ही उससे 4000 रुपये की मांग कर डाली। महिला ने अपनी ग़रीबी का हवाला देते हुए कहा कि यदि इतने पैसे होते तो बीके में ही आना था क्या, कहीं और प्राइवेट में न करा लेते डिलीवरी। लेकिन जब कर्मचारी नहीं माने व डराने-धमकाने लगे तो उर्मिला रोती-पीटती सीधे सिविल सर्जन गुलशन अरोड़ा के दफ़्तर में पहुंच गयी। अरोड़ा ने ड्रामा करते हुए महिला को चार हज़ार रुपये देकर कहा कि ये रुपये उन्हें दे दो तो वे उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेंगे।

लेकिन कर्मचारी इतने बेवकूफ़ नहीं थे, जब महिला उनकी शिकायत करने की चेतावनी देकर गयी थी और रुपये लेकर आ रही है तो उनको शक होना स्वाभाविक ही था। इसके अलावा डॉ. अरोड़ा जब खुद लूट-कमाई में साझीदार हैं तो क्या उनके दफ़्तर से वार्ड कर्मचारियों को सचेत नहीं कर दिया गया होगा? इसी के चलते कर्मचारियों ने पैसे लेने से इन्कार कर दिया। दिखावे के लिये डॉ. अरोड़ा ने एक जांच कमेटी का ड्रामा रच दिया है। इस तरह की जांचों का न पहले कोई परिणाम निकला है न भविष्य में कुछ निकलने वाला है। परिणाम केवल तभी निकल सकता है जब सिविल सर्जन खुद ईमानदार हो और राजनेता बेईमानों व निकम्मों को संरक्षण देना बंद कर दें।

नगर निगम का ऑडिट: फिलहाल निगमायुक्त ने चोरों की दाढी पकड़ी

फ़रीदाबाद (म.मो.) नगर निगमायुक्त मोहम्मद शाहीन द्वारा बीते 24 वर्ष का ऑडिट कराने का फ़ैसला वास्तव में ही स्वागत योग्य है। अब तक निगम के अधिकारी सारे राजस्व, ग्रांटें, कर्जे व जायदादें बेच कर डकार जाने के बावजूद सदैव, कंगालों की तरह हाथ फ़ैलाये ही खड़े रहते आये हैं। इन्ही हरामखोर एवं रिश्वतखोर अधिकारियों की बातों में आकर निगमायुक्त शाहीन ने भी निगम की जायदाद बेचने की सोच बना ली थी। इसके अलावा घरों में लगे बिजली मीटरों पर अलग से कर लगाकर हज़ारों करोड़ का राजस्व जुटाने की योजना भी बना ली थी।

ऐसे में यकायक उनका ध्यान ऑडिट की ओर जाना और वह भी 24 वर्ष पीछे तक का, शहर की जनता के लिये एक बड़ी राहत की उम्मीद जगाता है। **'मज़दूर मोर्चा'** हमेशा से लिखता आ रहा है कि निगम का राजस्व जुटाने वाला स्टाफ़ इसकी उगाही को डकार जाता है और कामों पर खर्च करने वाला स्टाफ़ एक रुपये के काम पर दस रुपये का खर्च दिखा कर डकारने में जुटा है। ऑडिट द्वारा सारा घोटाला सामने आ जायेगा, किसने राजस्व उगाही में कितना डकारा है और किसने कामों को करने में क्या-क्या घपले किये हैं।

शहर का दुर्भाग्य यह रहा है कि आज तक किसी भी आयुक्त एवं उसके ऊपर के उच्चाधिकारियों एवं राजनेताओं ने निगम में हो रही चौतरफ़ा लूट की ओर ध्यान देकर बही-खाते जांचने की जरूरत महसूस नहीं की। जब भी निगम का काम धनाभाव के कारण रुकने लगा तो तुरन्त ग्रांट, कर्ज व अन्य स्रोतों से धन उपलब्ध करा दिया गया। किसी ने यह सोचने समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया कि आखिर राजस्व कम क्यों आ रहा है और आया हुआ राजस्व जा कहां रहा है? अब भी धनाभाव के गंभीर संकट से निपटने के लिये पहले धन के अतिरिक्त साधन जुटाने की बात सोची गयी थी, परन्तु बाद में पैंतरा बदल कर ऑडिट कराने का फ़ैसला लिया गया। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे निगमायुक्त की धर्मपत्नी की समझ भी यकीनन हो सकती है। वे भारतीय एकाऊंट्स एंड ऑडिट सेवा की एक उच्चाधिकारी हैं। समझा जा रहा है कि उन्ही महोतरमा के सक्रिय सहयोग से एक अच्छी व ईमानदार ऑडिट पार्टी, भ्रष्टाचारियों की मांद रूपी नगर निगम में घुस कर उनका बखिया उधेड़ेगी।

तिकोना पार्क स्कूल के बगल में निगम के प्लाट पर दसियों साल से पड़ा बीसियों लाख का लोहा। ऐसी कितनी ही निगम की सम्पति ऑडिट के इंतजार में।

परन्तु सवाल यह पैदा होता है कि जिन राजनेताओं और अफ़सरों के संरक्षण में यहां लूट मची रही क्या वे इस तरह का ऑडिट कराने के लिये मोहम्मद शाहीन को यहां टिके रहने देंगे? दूसरा सवाल यह भी है कि ऑडिट में पकड़े जाने वाले घोटालेबाज़ों से क्या कोई रिकवरी कभी हो पायेगी?

800 से अधिक डिलिवरी हर महीने होती हैं बीके अस्पताल में

तिगांव सहित ज़िले की लगभग तमाम डिस्पेंसरियां व प्राइमरी हेल्थ सेंटर फ़र्जीवाड़े में जुटी हैं। यदि ये तमाम सेंटर अपना-अपना काम सही ढंग से करें तो प्रसव हेतु 20-20 किलोमीटर से चलकर लोगों को बीके में न आना पड़े जिसके परिणामस्वरूप यहां का काम आधा घट सकता है। लेकिन ज़िले के सिविल सर्जन व स्थानीय राजनेताओं की मिलीभगत से उक्त सेंटरों में कोई काम नहीं हो पा रहा। गत माह स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर तिगांव में एक बड़े अस्पताल की आधारशिला का ड्रामा करने तो जा पहुंचे, लेकिन वहां पहले से ही मौजूद पीएचसी के काम-काज को दुरूस्त कराने पर ध्यान नहीं दे सकते।

प्रसूति विभाग एवं वार्ड को देखने के लिये 8 महिला विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। ये न तो कभी ओपीडी में मरीज़ देखती हैं और न ही कभी रात की ड्यूटी में रहती हैं। और तो और कॉल (बुलावा) ड्यूटी पर भी नहीं आतीं। दरअसल माला व रजनी नामक दोनों नर्सों ने इन्हें आश्वस्त कर रखा है कि इन्हें कॉल पर आने की जरूरत ही नहीं है, आराम से घर पर सोयें।

सर्वविदित है कि इस अस्पताल में वही आता है जो इतना ग़रीब होता है कि कहीं और जाने लायक नहीं होता। इस दबे-कुचले तबके पर इन बेरहम डॉक्टरों व नर्सों की दादागिरी बेरोक-टोक चलती है, न कोई सुनने वाला न कोई पूछने वाला। कोई हो भी कैसे सकता है जब स्थानीय विधायकों एवं भाजपा सरकार के आशीर्वाद से गुलशन अरोड़ा जैसा निकम्मा व भ्रष्ट सिविल सर्जन यहां गत 3 वर्षों से तैनात हो।

हर माह 800 से अधिक डिलिवरियां बीके में होने से गुलशन अरोड़ा को दोहरा लाभ है। इन डिलिवरियों से होने वाली लूट कमाई में से जो हिस्सा मिलता है वह तो मिलता ही है, ज़िले भर की डिस्पेंसरियों में तैनात स्टाफ़ काम न करके जो फ़रलो मारता है उसके एवज में भी अरोड़ा जी की अच्छी खासी 'सेवा-पानी' हो जाती है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06